

अनुगामिनी

पूर्वी एशियाई देशों का प्रवेश द्वारा होगा मणिपुर : पीएम मोदी

8

अतीक, आजम और मुख्तार सपा-बसपा की सरकार में लोगों को करते थे परेशान : शह 3

अत्याधुनिक खेती पद्धति को अपनाएं किसान : सीएम गोले

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 22 फरवरी । राज्य कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग के तत्वावधान में तादोंग स्थित सोकें थांग में अत्याधुनिक तकनीकी आधार पर किए जाने वाली खेती हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स तथा रुफ टप (टेरेस) फार्मिंग के लिए चेताना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) मुख्य अधिकारी के रूप में उपस्थित थे। इसके साथ ही कृषि विभाग के मंत्री लोकनाथ शर्मा, विद्युत विभाग के मंत्री एमएन शेर्पा, क्षेत्र विधायिकों से अपील की गयी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि विद्यार्थी के बाल रोकना की गयी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि विद्यार्थी के बाल रोकना की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि विद्यार्थी के बाल रोकना की गयी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि विद्यार्थी के बाल रोकना की गयी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि विद्यार्थी के बाल रोकना की गयी।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री

गोले ने कहा कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि होने के बाद राज्य में पर्याप्त उत्पाद नहीं होगा। इसे ध्यान में रखकर अत्याधुनिक प्रविधि युक्त खेती की ओर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने पहल आरंभ किया है। ग्रामीण क्षेत्र में किसान खेतों में खेती करते हैं लेकिन शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए इस प्रणाली को प्रयोग में लाना होगा। इससे सब्जी उत्पादन में कमी नहीं होगी। उन्होंने जीएमसी से अपील की है कि शहरी क्षेत्र में इस प्रणाली को लेकर लोगों को जागरूक कराएं।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि विद्यार्थी के बाल रोकना की गयी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि विद्यार्थी के बाल रोकना की गयी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि विद्यार्थी के बाल रोकना की गयी।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री



अपील की।

एसकेएम प्रचार प्रसार सचिव रंजना प्रधान के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कार्यक्रम के पूर्ण मुख्यमंत्री गोले ने प्रदर्शनी में रखे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स तथा रुफ टप फार्मिंग खेती नमूनों की अवलोकन की। हाइड्रोपोनिक्स की भरोसे में न रहने की उन्होंने

अर्थात मिट्टी रहित पानी से होने वाली खेती, एक्वापोनिक्स खेती मछली पालन के साथ सब्जी खेती यह अत्याधुनिक प्रविधि और टेरेस फार्मिंग अर्थात घर के छत पर किए जाने वाली खेती विषय में विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी।

दूध की कीमत को लेकर बीजेपी विधायक थापा ने सरकार को घेरा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 22 फरवरी । अपर बुर्तुक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक डीआर थापा ने दूध की कीमत को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और विधानसभा में उसकी ओर से दिखाए गए दस्तवेजों को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की है।

यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में विधायक थापा ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में मैंने विधायक की हीसियत से सरकार से सिविकम के कृषि विकास को लेकर सरावल किया था। इसके जबाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविकम के कृषि विकास को लेकर सरावल किया था। इसके जबाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविकम के कृषि विकास को लेकर सरावल किया था। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि विद्यार्थी के बाल रोकना की गयी। उन्होंने उसकी ओर से दिखाए गए दस्तवेजों को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की है।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि दूध की कीमत बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने उसकी ओर से दिखाए गए दस्तवेजों को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की है।

विधायक थापा ने कहा कि यह सरकार और विभाग की जिम्मेदारी है इस बारे में वह स्पष्ट करे। आज ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निम्न वर्ग के किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वे भ्रम की स्थिति में हैं और सरकार तथा विभाग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। सरकार की ओर से इस बारे में कोई भी



सिविकम हमेशा से एक ट्रेंडसेटर रहा है : सीएम गोले



अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 22 फरवरी । राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग 2022-23 आयोजन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री गोले ने मुख्य अधिकारी की अविधि का अनुर्जित करने के लिए एक अधिनव कार्यक्रम होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि विद्यार्थी के बाल रोकना की गयी। उन्होंने उसकी ओर से दिखाए गए दस्तवेजों को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की है।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि दूध की कीमत बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने उसकी ओर से दिखाए गए दस्तवेजों को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की है।

इसके अलावा, आज दो और परियोजनाओं का शामिल किया गया। उन्होंने आगे कहा कि सिविकम हमेशा से एक ट्रेंडसेटर रहा है और ऐसा ही एक क्षेत्र है धारा विकास योजना। धारा विकास सिविकम राज्य में सूखे झरने को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए एक अधिनव कार्यक्रम है।

कार्यक्रम ने राज्य के लिए एक ग्राम स्थिर्गत एटलस और एक जल स्रोत एटलस विकासित करने पर भी काम किया है। मुख्यमंत्री गोले ने कहा कि यह परियोजना भी नावार्ड द्वारा वित्त पोषित और समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि नावार्ड ने सिविकम के लिए जलावाहु परिवर्तन के लिए राशी अनुकूलन कोष जैसे फंड भी लाए हैं।

अपने संबोधन में कृषि एवं बागवानी विभाग के मंत्री लोकनाथ शर्मा ने ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नावार्ड द्वारा किए गए योगदान के बारे में बताया।

उन्होंने राज्य फोकस पेपर 2022-23 जारी करने के लिए नावार्ड ने कार्यक्रम के महा प्रबंधन आदि उपरिक्त थे। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री गोले ने रेस्टेट फोकस पेपर 2022-23 जारी किया गया। इस अवसर पर नावार्ड एसीएम भाषा देते हुए नावार्ड ने स्टेट फोकस पेपर प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने साल 2022-23 के लिए राशी क्षमता अनुमान लिया गया। इसके अनुरूप राज्य की अधिकारी ने एक अधिनव कार्यक्रम के लिए एक ग्राम स्थिर्गत एटलस के लिए एक जल स्रोत एटलस विकासित करने के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्यक्रम का अवधारणा की गयी।

उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अधिनव कार्य

देवरिया में विपक्षियों पर बरसे नड़ा

बोले- सपा शासन में माफिया-बाहुबली दन-दनाते थे, अखिलेश ने आंखों में बांध रखी थी पट्टी

देवरिया, 22 फरवरी (एजेन्सी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़ा ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधा और कहा कि सपा शासन में यूपी में माफिया-बाहुबली दन-दनाते थे। लेकिन अखिलेश ने आंखों में पैंपट बांध रखी थी। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद माफिया-बाहुबली जेल में बंद हैं।

नड़ा आज देवरिया जिले के रुद्रपुर विस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व राज्यमंत्री जय प्रकाश निषाद के समर्थन में रुद्रपुर के सतासी राज इंटर कालेज मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश के शासनकाल में रामपुर में सीआरपीएफ केंप पर गोलियां चलाई गई। उन आतंकवादियों को जवाब देना है। कहा कि योगी जी ने यूपी से माफियाराज समाप्त किया, गुंडाराज समाप्त किया और

देशद्रोहियों को जेल में डाला। हमने तय किया है कि देवबंद, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएं।

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के शासन में यूपी में करीब 200 दंगे हुए। पिछले 5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सपा सरकार कैरेना से लोग पलायन कर गए। वो कहते हैं यह अतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है। अयोध्या व वाराणसी में बम ब्लास्ट हुए थे। मुख्यमंत्री मुकदमे वापस लिए और आतंकियों को छोड़ दिया। अखिलेश रक्षक नहीं, भक्षक हैं। आतंकवादियों की रक्षा करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अखिलेश यादव अतंकियों की रक्षा करेंगे।

नड़ा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज खत्म कर आर्थिक स्थिति सुधारी है। मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को सातवें से दूसरे स्थान पर खड़ा किया। योगी ने गुंडाराज समाप्त किया। देवबंद, मेरठ, कानपुर बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएं।

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के शासन में यूपी में करीब 200 दंगे हुए। पिछले 5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सपा सरकार कैरेना से लोग पलायन कर गए। वो कहते हैं यह अतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है। अयोध्या व वाराणसी में बम ब्लास्ट हुए थे। मुख्यमंत्री मुकदमे वापस लिए और आतंकियों को छोड़ दिया। मोदी की सरकार आई अनुच्छेद 370 हटाई गई। मोदी के नेतृत्व में तीन तलाक का कानून समाप्त हुआ। यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान में नहीं है। यह होता है वोट का कमाल। कहा कि पहले भी दिवाली आती थी अयोध्या में दिवाली क्यों नहीं मनती थी। यज श्री राम का नारा सदियों से लग रहा है। मोदी की सरकार बनी तो मंदिर की राह आसान हुई। मंदिर बन रहा है।

नड़ा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज खत्म कर आर्थिक स्थिति सुधारी है। मुख्यमंत्री योगी

रुस-यूक्रेन विवाद में भारत आ रही सूरजमुखी तेल की खेप में देरी संभव

चेन्नई, 22 फरवरी (एजेन्सी)। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए नियमों में दील देने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के अनुसार जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से गेड़ों की इजाजत दी रही है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, उपीदवारों की बैठकों, रेलियों, रोड शो के लिए 50 फीसदी क्षमता की पाबंदी की अब हट दिया है। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण की ध्यान में रखते हुए रेली कई प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि, बीच में भी चुनाव आयोग ने नियमों में दील देते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ रेली करने की अनुमति दी थी।

इससे पहले रविवार को चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के लिए स्टर प्रचारकों की संख्या के संबंध में बड़ी राहत दी थी। कोविड-19 मामलों में गिरावट का चलाना देते हुए, चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के लिए स्टर प्रचारकों की संख्या को बहाल कर दिया था। जिससे अब सभी पार्टियों नियम के मुताबिक पहले जितनी संख्या में स्टर प्रचारकों को मैदान में उतार सकती हैं। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीती दल अधिकतम 40 स्टर प्रचारकों को मैदान में उतार सकते हैं। अब पार्टियों जो पंजीकृत हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनके पास अब 20 स्टर प्रचारक हो सकते हैं।

बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार पांच राज्यों में कुल सात चरणों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था। इसमें से अब तक तीन चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब चार चरण के चुनाव बचे हुए हैं। इसमें चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को, पांचवें चरण के लिए 7 फरवरी को, छठवें चरण के लिए 3 मार्च और सातवें चरण के लिए 7 मार्च को बोट डाले जाएंगे।

पेगासस जासूसी मामले पर जांच समिति की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, शुक्रवार को सुनवाई

उनके मुताबिक यूक्रेन संकट से सूरजमुखी तेल की खुदरा कीर्तीमानों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि तब अर्जेंटीना और रूस से तेल खरीदा जा सकता है। उन्होंने हालांकि उम्मीद जतायी है कि अब चार चरण के लिए सूरजमुखी का बड़ा उत्पादक है।

याद्य तेल उत्पादक कंपनियों ने यूक्रेन संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है और उनका मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच अलग गोल्ड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधाकर देसाई ने आईएनएस को बताया कि भारत हर मह करीब 42 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात करता है और कभी-कभी यह अपूर्ण रहता है। उन्होंने तेल खरीदा जा सकता है।

देसाई के मुताबिक भारतीय आयातक यूक्रेन के विकल्प के रूप में रूस और अर्जेंटीना को देख सकते हैं। यूक्रेन को तरह रूस भी सूरजमुखी का बड़ा उत्पादक है।

देसाई के मुताबिक भारतीय आयातक यूक्रेन के विकल्प के रूप में रूस और अर्जेंटीना को देख सकते हैं। यूक्रेन को तरह रूस भी सूरजमुखी का बड़ा उत्पादक है।

देसाई ने कहा कि अगर यूक्रेन संकट दो से तीन सालों और जारी रहता है तो इसका दबाव भारतीय आयातक यूक्रेन के बीच का कमीत अवधिक रूप से देखा जा सकता है। इनकी वैशिक कीमत 1,500 से 1,525 डॉलर प्रति टन के करीब है।

यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक यूक्रेन के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार 2019-20 के दौरान 2.52 अरब डॉलर का था, जिसमें 463.81 अरब डॉलर का नियांत और 2,060.79 अरब डॉलर का आयात शामिल है।

यूक्रेन को दबाव देने के लिए यह अपूर्ण रूप से सूरजमुखी तेल को लेकर रखना नहीं हो पाया है। सूरजमुखी तेल का देश का सबसे बड़ा बाजार दक्षिण भारत है।

भारत से यूक्रेन को दबाव, रिएक्टर/ब्यॉर्यतर मशीन, मर्शीनी सामान, तिलान, फल, कॉफी, चाय, मसाले, लौह अयरक, स्टील आदि का नियांत किये जाते हैं जबकि भारत वहाँ से मुख्य रूप से सूरजमुखी तेल, अकार्बिंत रसायन, आयरन, स्टील, खालिस्ट्रिक, रसायन आदि का आयात करता है।

एशिया प्रशांत में भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा आयातक देश है जबकि विश्व स्तर पर इसका पांचवां दर्द है।

नई दिल्ली, 22 फरवरी (एजेन्सी)। पेगासस जासूसी मामले पर जांच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।

अयोध्या, 22 फरवरी (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और बहराइच जामा पार्टी (बजप) को बैठक आयोग की ध्यान में रखते हुए बहराइच के लिए लोटपोल को घोषित किया।

योगी ने कहा कि अब चार चरण के लिए तरसाया है और अब मोदी की राजनीति को बदलना चाहिए। उन्होंने बहराइच के लिए लोटपोल को घोषित किया।

योगी ने कहा कि अब चार चरण के लिए तरसाया है और अब मोदी की राजनीति को बदलना चाहिए। उन्होंने बहराइच के लिए लोटपोल को घोषित किया।

योगी ने कहा कि अब चार चरण के लिए तरसाया है और अब मोदी की राजनीति को बदलना चाहिए। उन्होंने बहराइच के लिए लोटपोल को घोषित किया।

योगी ने कहा कि अब चार चरण के लिए तरसाया है और अब मोदी की राजनीति को बदलना चाहिए। उन्होंने बहराइच के लिए लोटपोल को घोषित किया।

योगी ने कहा कि अब चार चरण के लिए तरसाया है और अब मोदी की राजनीति को बदलना चाहिए। उन्होंने बहराइच के लिए लोटपोल को घोषित किया।

योगी ने कहा कि अब चार चरण के लिए तरसाया है और अब मोदी की राजनीति को बदलना चाहिए। उन्होंने बहराइच के लिए लोटपोल को घोषित किया।

योगी ने कहा कि अब चार चरण के लिए तरसाया है और अब मोदी की राजनीति को बदलना चाहिए। उन्होंने बहराइच के लिए लोटपोल को घोषित किया।

योगी ने कहा कि अब चार चरण के लिए तरसाया है और अब मोदी की राजनीति को बदलना चाहिए। उन्होंने बहराइच के लिए लोटपोल को घोषित किया।

योगी ने कहा कि अब चार चरण के लिए तरसाया है और अब मोदी की राजनीति को बदलना चाहिए। उन्होंने बहराइच के लिए लोटपोल को घोषित किया।

योगी ने कहा कि अ

अतीक, आजम और मुख्तार सपा-बसपा की सरकार में लोगों को करते थे परेशान : शाह

प्रतापगढ़, 22 फरवरी
(एजेंसी) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विषयकी दलों पर निशाना साधा और कहा कि अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी सपा, बसपा के शासन काल में सबको परेशान करते थे, आज जेल में हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को बुधवार को रामीगंज विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि तीन चरणों का मतदान हो चुका है। यूपी से सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है। 300 से अधिक सीटों के साथ भाजपा सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश बाबू अच्छे गेंदबाज नहीं हैं। यह फुलटास बाल मिले तो चौका लगाना ही चाहिए। कहा कि योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का काम किया है। अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी सपा बसपा के शासन काल में सबको परेशान करते थे। आज ये सब जेल में हैं। अगर आपने गलती से भी अखिलेश की सरकार लाई, तो ये जेल में रहेंगे क्या?

अमित शाह बोले कि अखिलेश बाबू आज मैं हिसाब देने और आपसे हिसाब मांगने भी आया है। एक करोड़ 67 लाख लोगों को क्री रसई गैस कनेक्शन मिले। भाजपा की सरकार बनते ही होली में फ्री में गैस सिलेंडर घर पहुंच जाएगा।



महिलाओं को शर्म न महसुस हो इसलिए भाजपा ने बड़ी संख्या में शौचालय बनवाए।

उन्होंने कहा कि सपा-बसपा-कांग्रेस जो जातिवाद, परिवारवाद के आधार पर चलती हैं, ये उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। इनके शासन में घोटालों के गढ़, परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर, माफियाओं को टोल वसूली रही। इन्होंने गरीबों, पिछड़े और महिलाओं के लिए न-एंट्री कर दी थी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के समय में शौचालय नहीं बनाए गए। महिलाओं के सम्मान की बात सोची भी नहीं। फले बिजली आती ही

नहीं थी अब बिजली ही नहीं मिलती बल्कि गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन फ्री दिया जा रहा है। एक बार फिर सरकार बनाइए, पांच साल तक किसानों को बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा।

शाह बोले कि यह माफिया का क्षेत्र है, हमारे सांसद साथी संगम लाल अक्सर दबंगों की चार्चा करते

थे। योगी जी ने माफिया पर नकेल करार करोड़ की जमीन भूमाफिया क्षेत्र थे, अब वह गरीबों को मिल रही है। भाजपा ने जातिवाद, परिवारवाद, उत्तीकरण खत्म किया।

युधमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पर्टी ने कई सालों तक देश पर राज

किया। उन्होंने जगजीवन राम जी और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने के अलावा कुछ नहीं किया। इतने साल हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर जो को भारत रव नहीं मिल था, जब कांग्रेस पार्टी गई, तब बाबा साहब को भारत रव देने का काम हुआ।

कहा कि पिछली सरकारों ने, कुंभ हो या अर्ध कुंभ, सभी में घोटाले और अव्यवस्थाएं की थीं। 2019 में योगी जी ने यहां भव्य कुंभ का आयोजन करार पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम किया। अर्ध कुंभ में 71 से ज्यादा देशों के राजदूत संगम में आए थे।

आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ थी सपा सरकार : पीएम मोदी

बहराइच, 22 फरवरी
(एजेंसी) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सपा सरकार, आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने तक से खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते।

प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को बहराइच में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों पर यूपी में एक नहीं बल्कि कई-कई बम धमाकों का आरोप था, ये लोग उन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने का पक्षा निर्णय ले रहे थे। ये आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलाना चाहते थे। समाजवादी सरकार, आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने तक से खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते।

मोदी ने कहा कि इन लोगों ने

दशकों तक गरीबी हड्डी और समाजवाद के नाम पर बोट बटोरे परिवारवादियों को हासने की तैयारी कर चुके हैं। मोदी ने कहा कि यूपी में आपके लिए नए रास्ते खुल रहे सत्ता में रहे लोगों ने गरीबों को गरीबी से लड़ने के लिए न अब दिये न साक्षर दिये। हाय लोगों ने गरीबों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिये। जनधन खाते के साथ मोबाइल को जोड़ने से सुरक्षा चढ़ मजबूत हो गया। आप जितनी ताकत हमें देंगे, हम उतने ही मजबूत फैसले लेंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा की योजनाओं का बद्धान करते हुए कहा कि दोबारा सपा की सरकार बनी तो योजनाएं बंद हो जाएंगी।

मोदी ने कहा कि यहां गरीबों को मौका मिला तो ये लोग गांव गरीब की योजनाओं को बंद कर देंगे। इन्हें मौका मिला तो बदला लेने की फिरक में हैं। ये आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलाना चाहते थे। समाजवादी सरकार, आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने तक से खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग

प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी के लोगों ने लागतार तीन बार (2014, 2017, 2019) में परिवारवादियों को देखा है। इस बार भी भारत का ताकतवर हो गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी के

पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। आज आपका एक-एक बोट भारत को ताकतवर बनाएगा। हमने तमाम संघर्षों से लोहा लेते हुए, आजादी से यहां तक का सफर तय किया है। हाय साल में भारतीय व्यवस्था की स्थिति सुधारी जा रही है। पांच साल में भारतीय एक विकासित और समृद्ध भारत है। इस समृद्ध भारत के लिए उत्तर प्रदेश के लिए तक्से दे रही है। पांच लाख लोगों को मुद्रा योजना और स्टार्टअप के लिए देंगे। यह सब बिना भेदभाव और बिना तुष्टिकरण हो रहा है।

मोदी ने कहा कि हमारी सरकार संकाठ के समय कभी भी किसी का साक्षर नहीं छोड़ती, बल्कि गरीब परिवार का संबल बनकर खड़ी भी एक योजना के लिए केवल 90 दैसे और दूसरी योजना के लिए एक महीने का एक रुपये रखा गया। इन योजनाओं के माध्यम से गरीब को दो-दो लाख रुपये का सुरक्षा करवा दिया गया। यूपी के साढ़े चार करोड़ गरीब इस योजना से जड़े हुए हैं। इस योजना से गरीबों को एक हजार किया है।

कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना, भारत और

करोड़ की मदद मिली है।

बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 22 फरवरी
(एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सभी राज्य बोर्डों, सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईआईएस द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10 और 12 की ऑफलाइन परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की गई है।

याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, जो पिछले साल परीक्षाओं के लिए सीबीएसई के 30:30:40 वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर परीक्षाओं के संचालन की देखरेख कर रहे थे।

अधिकारी प्रशांत पद्मानाथन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईआईएस और राज्य बोर्ड में पढ़े जाए कई छात्रों ने याचिकाकार्यालय शासन काल में सम्पादित विभिन्न राज्यों से उन मुद्दों के लिए संपर्क किया, जो बोर्ड विभिन्न राज्यों के समक्ष मामले को ताकतवर बनाना चाहते थे। इस जनहित याचिका के द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10 और 12 की ऑफलाइन परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है।



याचिका के अनुसार, 'अन्य याचिकाकार्ता छात्रों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के माता-पिता भी हैं, जो बोर्ड के फैसले से व्यवहृत हैं।' इस परीक्षा में प्रदर्शन के लिए जो मानसिक दबाव बनाया जाता है, वह इतना अधिक है कि हर साल कई अनुचित होगा, बल्कि यह बिल्कुल अपराध की रक्षा करना आवश्यक किया। पीठे ने निर्देश दिया कि याचिका की एक अप्रिम प्रति

सीबीएसई को दी जाए। याचिका में कहा गया है, 'कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने के अतिरिक्त डर के साथ छात्रों को परीक्षा में शामिल होना और उनका सामना करना न केवल अनुचित होगा, बल्कि यह बिल्कुल अधिकारियों को एक अधिसूचना पारित करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था।'

याचिकाकार्ताओं ने तक दिया कि उनका दावा वास्तविक है और परीक्षा के लिए जो उनका दावा वास्तविक है वह इस देश के विभिन्न हिस्सों के उन छात्रों की सूची भी शामिल है, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा के मुद्दों के संबंध में सहाय देश के अधिकारियों के द्वारा देखरेख किया था।



GOVERNMENT OF SIKKIM EAST DISTRICT ZILLA PANCHAYAT RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT GANGTOK, SIKKIM

NIT No.: 01(A)/SE(N/E)/EDZP/JJM/2021

शिवमोगा में तनाव

सांप्रदायिकता जब अपना खेल खेलती है, तो आमतौर पर यही होता है। चंद दिनों के भीतर ही पूरा कर्नाटक सूखे फूस के ढेर-सा लगने लगा है, जहां हर चिनगारी अब डराती है और हर घटना आग में घी डालती हुई दिखती है। राज्य के शिवमोगा जिले में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद पूरे कर्नाटक में जो तनाव सतह पर उभर आया है, वह पूरे देश में ही सिहरन पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में, जहां इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहां इस तरह की खबरें नई परेशानियां भी खड़ी कर सकती हैं। हम अभी नहीं जानते कि इस हत्या का ठीक-ठीक कारण क्या था, लेकिन जो हालात हैं, उनमें इस मामले को राज्य में चल रहे हिजाब-विवाद से जोड़कर देखा जाना स्वाभाविक है। अगर यह मामला हिजाब विवाद से नहीं भी जुड़ा हो, तब भी यह विवाद को और भड़काने का काम तो करेगा ही। और अगर यह हत्याकांड हिजाब विवाद से जुड़ा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि राजनीति एक बेवजह विवाद को निर्माता की हड तक खींचकर ले गई है। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो इसे किसी भी तरह हिजाब विवाद से जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनके राजनीतिक हित ऐसे ही विवादों से सध्यते हैं। यही वजह है कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचे, उससे पहले ही आरोपों का ढेर लग गया है।

प्रशासन ऐसे मौकों पर खास तरह से काम करता है और उस तरह के कदम उठाए जाने की खबरें भी आ रही हैं। मूल रूप से यह विवाद स्कूल, कॉलेजों से शुरू हुआ था, इसलिए ऐसे सभी शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जिन इलाकों में तनाव बढ़ने की आशंका है, पुलिस ने उन सभी इलाकों की बैरीकेंडिंग कर दी है। ऐसे प्रयासों के पीछे दरअसल कोशिश यही रहती है कि अगर कुछ लोगों में गुस्सा है या फिर किसी किसकी अफवाहें वैगैरह अगर लोगों को उत्तेजित कर रही हैं, तो टकराव की आशंकाओं को लगातार कम किया जाए। लेकिन ऐसे ही मौके पर हमें राज्य के एक मंत्री का ऐसा बयान सुनाई देता है, जो प्रशासन के इन प्रयासों पर पानी फेर सकता है।

बेशक, आग में घी डालने वाले और भी हैं। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है, वह बताता है कि किसी भी तनाव के बाद शांति कायम करने वाले लोग समाज में लगातार कम होते जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के ऐसे बयान लगातार ही सुनाई दे रहे हैं, जो विवाद को किसी भी तरह से ठंडा नहीं होने देंगे। इन सबकी शह पर कुछ ऐसे संगठन भी सक्रिय हैं, जो एक नितांत संवेदनशील मुद्रे का निपटारा सङ्कोचों पर ही कर लेना चाहते हैं। समाज के बुद्धिजीवी तबके ने भी सब कुछ अदालत के भरोसे छोड़ दिया है। मुमकिन है कि अदालत हिजाब विवाद को किसी अंजाम तक पहुंचा दे, लेकिन इस बीच जो तनाव बढ़ेगा, हो सकता है, कल को वह भड़कने का कोई और बहाना खोज ले। इसलिए प्राथमिकता इसी तनाव को घटाने की होनी चाहिए। अचानक ही हमारा पूरा समाज उस मोड़ पर पहुंच गया है, जहां सहिष्णुता की बात करने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। इन स्थितियों को अगर जल्दी से जल्दी नहीं बदला गया, तो आज हम जो कर्नाटक के स्तर पर देख रहे हैं, वही हालात हमें देश के दूसरे हिस्सों में भी परेशान कर सकते हैं।

संपादकीय पृष्ठ

रोजगार पैदा करने का कौशल

पत्रलेखा चर्टर्जी

देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहां लगभग ब्राजील की ही तरह 53.5 बीस करोड़ लोग रहते हैं। दांव असाधारण रूप से उंचा है। कहने की जरूरत नहीं कि इस विधानसभा चुनाव की नतीजा 2024 के लोकसभा चुनावों से अलग एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो उत्तर प्रदेश के भविष्य को आकार देगा, चाहे कोई भी निर्वाचित हो। वह है—उत्तर प्रदेश के बच्चों और युवाओं की स्थिति।

हालांकि इस संधूम में हाल के वर्षों में सुधार और पहल हुई है, लेकिन स्थिति चुनौती पूर्ण है। कोरोना वायरस महामारी ने भारत के बच्चों और युवाओं के प्रारंभिक वर्षों को बुरी तरह प्रभावित किया है, साथ ही पहले से मौजूद उनकी समस्याओं को और बदल बनाया है। लोकसभा चुनावों में असुरक्षा की भावना कि एक शिक्षित युवा को न तो नौकरी मिल पाएगी और न ही वह खेतों के पारिवारिक पेशे में शामिल हो पाएगा।

इसलिए स्पष्ट रूप से यह आवश्यक है कि अभिभावकों और बच्चों की कार्यसंलग्न के साथ एक प्रमुख घटक और व्यावसायिक कौशल के साथ-साथ में योग्य बच्चों को वित्तीय सहायता पाने के अवसरों के रूप में जिला विशिष्ट हस्तक्षेप किया जाए। राज्य में युवाओं के लिए प्रमुख मुद्दा और उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले प्रयोक्त 1,000 बच्चों में से लगभग 60 बच्चे अपना पांचवां जन्मदिन नहीं देख पाते हैं, हालांकि यह स्थिति 2015-2016 से बेहतर है, जब प्रति 1,000 बच्चों के जम पर मृत्यु दर 78.1 थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश में खालों बच्चे जो जीवित बच जाते हैं, वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। सिन्हर, 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 35 अतिरिक्त संस्थानों को विवादों से सध्यते हैं।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश में खालों बच्चे जो जीवित बच जाते हैं, वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। सिन्हर, 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 35 अतिरिक्त संस्थानों को विवादों से सध्यते हैं।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अस्वीकार्य रूप से उच्च है।

उत्तर प्रदेश के जम पर मृत्यु दर 78.1

थी, लेकिन यह अब भी अ



ड्राइविंग के क्षेत्र में दो तरह से कैरियर बनाया जा सकता है। मसलन, आप स्वयं के व्यवसाय के स्थानी और चालक हो सकते हैं। इसके लिए आप ओला और उबर के तहत पंजीकृत कुछ टैक्सी प्राप्त करें और इस उद्योग के माध्यम से भी अच्छी कमाई करें।

कैरियर के लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है ड्राइविंग

ड्राइविंग एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कैरियर बनाने के बारे में शायद ही कोई युवा सोचता हो। यकौनीन यह काफ़ी फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे कैरियर या व्यवसाय के रूप में देखते हैं तो इसमें भी आपके विकास की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा कैरियर औप्शन साबित हो सकता है, जो बहुत अधिक पढ़-लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी आमदनी करके एक बेहतर जिन्दगी जीना चाहते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस कैरियर के बारे में बता रहे हैं—

ऐसे बनाएं कैरियर

कैरियर एक सर्पर्ट बताते हैं कि ड्राइविंग के क्षेत्र में दो तरह से कैरियर बनाया जा सकता है। मसलन, आप स्वयं के व्यवसाय के स्थानी और चालक हो सकते हैं। इसके लिए आप ओला और उबर के तहत पंजीकृत कुछ टैक्सी प्राप्त करें और इसके लिए काम से भी अच्छी कमाई करें। इसके अलावा अगर आपके पास पर्सनल पैसा नहीं है तो इस रिंग्टिंग में आप कुछ ओला व उबर आदि में बौद्धि करार कार चालक अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं।

योग्यता

यह एक ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिसके लिए किसी खास प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता हो। आपको बस एक वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है और फिर काफ़ी ड्राइविंग स्कूल हैं जो आपको अपने आसापास के



एक अच्छा मिक्सोलॉजिस्ट बनने के लिए अच्छा श्रोता होना व फ्रेंशली होना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा एव्यूरेसी, बैहतर कम्युनिकेशन स्किल्स, आगोनाइजेशन स्किल्स, एनर्जेटिक, फलेविसिलिटी, टीमवर्क, व क्रिएटिविटी जैसे गुण आपके काम को आसान बनाते हैं।

अगर आप उनमें से हैं, जिन्हें नी से पांच की जॉब करना अच्छा नहीं लगता। आप अपनी लाइफ में लीक से बहकर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे में मिक्सोलॉजी के क्षेत्र में आपना कैरियर देख सकते हैं। यह एक बेहद आवश्यक है। डिक्टर कैरियर औप्शन है। एक मिक्सोलॉजिस्ट एक व्यक्ति है जो कॉकटेल और मिश्रित पेय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मादक पेय और अन्य सामग्री की मिलाता है। अमातौर पर लोग मिक्सोलॉजिस्ट को बार-टॉर ही समझते हैं, लेकिन इनमें अन्त है। बार-टॉर कैवल बार में होते हैं और कैवल पॉले से मौजूद डिंक्स को ही बनाते हैं। जबकि मिक्सोलॉजिस्ट एक नए तरह के कॉकटेल बनाता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको इस कैरियर के बारे में बता रहे हैं—

क्या होता है काम

एक मिक्सोलॉजिस्ट का काम बार-टॉर की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। वे कई तरह की डिस्क्रिप्शन की मिक्स करके एक नया पेय प्राप्त करने के अलावा, बार की आगोनाइज करना, कस्टरिंग को नए डिक्स के बारे में बनाना और उन्हें एंटरटेन करना, नए पेय प्राप्ती का सुझाव देना और मैंग में कुछ नए पेय पर्याप्ती को शामिल करना होता है। यह एक ऐसी

लाइफ संस्थान का काम है जो कॉकटेल के अंतर्गत काम करते हैं।

लेखपाल को कुछ राज्यों में पटवारी,

पटेल, कारनाम अधिकारी,

शानदार नीकरी से जाना जाता है। यह एक सरकारी काफ़ी काम कर सकते हैं और इसमें जॉब सिक्योरिटी, पैशन, पीएफ जैसे लाभ मिलते हैं।

आजकल अधिकतर युवा सरकारी नीकरी करना चाहते हैं। लेकिन सरकारी अमर आप चाहते हैं तो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में बौद्धि की काम कर सकते हैं और दूसरे लोगों को कार चालना सिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पर्सनल कार ड्राइवर की जरूरत होती है, आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं। लेखपाल लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं—

संभावनाएं

इस क्षेत्र में कैरियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है।

सबसे पहले तो आप ओला व उबर के

अलावा कई कस्टर्मर आपेंगी गाड़ी में कई कस्टर्मर आपेंगी, आपका उनके

प्रति व्यवहार के साथ होना आसान है।

यह एक सरकारी नीकरी है और इस रिंग्टिंग में बौद्धि की काम कर सकते हैं।

आपको बहुत कुछ लाभ मिलता है।

आपको बहुत कुछ लाभ मिलता ह

पूर्वी एशियाई देशों का प्रवेश द्वारा होगा मणिपुर : पीएम मोदी

इंफाल, 22 फरवरी (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर पूर्वी एशियाई देशों का प्रवेश द्वारा होगा, जिसके लिए पूर्वोत्तर राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और पूर्वी एशियाई देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आसान संपर्क के माध्यम से मणिपुर की स्थानीय व्यापारी और थाईलैंड से जोड़ा जाएगा।

मोदी ने इमफाल में एक चुनावी रेली को संबोधित करते हुए कहा, 'वह दिन दूर नहीं जब मणिपुर की राजधानी को ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में मणिपुर में 40 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी लागू की जा रही हैं।'

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के महाप्रबंधक अंगुल गुप्ता ने पहले कहा था कि भारत को पड़ोसी स्थानांतर से जोड़ने



के उद्देश्य से एक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 111 किलोमीटर इंफाल-मोरेंद्र खंड का अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

ओलंपियरों का जिक्र करते हुए (भारतीय मुकेबाजी के दिग्गज एम.सी. मैरी कॉम और भारोतोलक मौराबाई चानू) प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, 'भाजपा सरकार ने पहले ही राज्य में एक अनूठी खेल संस्कृति विकसित की है और मणिपुर देश के खेल क्रीड़ों में से एक होगा।'

मोदी ने कहा कि मणिपुर के लोगों की जनसांख्यिकी, संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं।

यह ओषण करते हुए कि केंद्र ने इससे प्रकाश डालते हुए प्रोत्साहित करते हुए किए गए वादों पर प्रतिवाद में आए।

और राज्य सरकार एमएसएमई क्षेत्रों का जोरदार समर्थन कर रही है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पाम तेल खेती मिशन भी शुरू किया है और इससे मणिपुर के किसानों को कार्यी हाद तक मदद मिलेगी।

यह कहते हुए कि भाजपा सरकार ने राज्य की लंबे समय से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं। भाजपा के चुनावी ओषण पत्र में आए।

आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों को एकजुट होना चाहिए : ओम बिरला

अबू धाबी, 22 फरवरी (एजेन्सी)। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैश्विक सुरक्षा और सतत विकास के लिए सभी देशों से एकजुट होकर आतंकवाद की चुनौतियों से लड़ने का आह्वान करते हुए संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में हुए आतंकी हमलों की कड़े और स्पष्ट शब्दों में निदा की है।

अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात की फेडरल नेशनल काउंसिल-संसद के छठे पूर्व असाधारण सत्र में सांसदों को सम्बोधित करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत और यूएई के लगातार मजबूत होते संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद के संबंध में दोनों देशों की साझी चिंता वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक परिवर्त्तन में हमारे सहयोग को नया रूप दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई की आधिकारिक साझेदारी क्षेत्रीय और वैश्विक समृद्धि का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है।

बिरला ने 3 ई अर्थात् एनजी, एकोनॉमी और प्रवासी के स्तरभौं पर भारत और यूएई के साझा हित और प्रगाढ़ होने का भी दावा किया। आपको बता दें कि ओम बिरला लोक सभा के पहले अध्यक्ष हैं जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की संघीय

राष्ट्रीय परिषद- संसद के सदस्यों को संबोधित किया है। यूएई के दोनों देशों के बीच व्यापक आधिक साझेदारी समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नया विरला ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों का सदैव विरोध किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और सतत विकास के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के सभी राष्ट्र आतंकवाद और हिंसक उत्तराधारी चुनौतियों से लड़ने के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा कि धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद से बढ़ते खतरों और तोणों की सुरक्षा के संबंध में भारत और यूएई की साझा चिंता वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक परिवर्त्तन में दोनों देशों के सहयोग को नया रूप दे रही है।

बिरला ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा और 2016 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारतीय समृद्धयोग देश के आधिक विकास के साथ-साथ दोनों



कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक आधिक साझेदारी समझौते ने सांसदों को संबोधित करते हुए एक नया आयाम देने के साथ साथ भावी आधिक विकास का आधार भी तैयार किया है।

उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देशों के बीच व्यापक आधिक साझेदारी समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम देने के साथ साथ भावी आधिक विकास का आधार भी तैयार किया है।

उन्होंने कहा कि विश्व के सभी राष्ट्र आतंकवाद के संबंध में दोनों देशों के साझी चिंता वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक परिवर्त्तन में हमारे सहयोग को नया रूप दे रही है।

बिरला ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा और 2016 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारतीय समृद्धयोग देश के आधिक विकास के साथ-साथ दोनों

देशों को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लोक सभा अध्यक्ष ने निवेशकों को भारत में निवेश के लिए लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत आज विश्व का अग्रणी इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है और डिजिटल इकोनॉमी, मानव संसाधन और स्मार्ट शहरीकरण की दिशा में कोई जाने वाली पहलों से उत्पन्न नए अवसरों का लाभ यूएई की कंपनियों तथा सकती है।

इससे पहले, संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष एच.ई. सकर गोबाबा ने साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए किए गए फैसलों का भी स्वागत किया। यूएई में रहने वाले प्रवासी समुदायों में से भारतीय समृद्धयोग देश को सबसे बड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय समृद्धयोग देश के नेतृत्व में यूएई के दौरे पर सकती है।

बिरला ने यूएई द्वारा पिछले वर्षों में लोकतंत्र को व्यापक आधार देने तथा संसद में महिलाओं की आयाम देने के साथ साथ भावी आधिक विकास का आधार भी तैयार किया है।

इससे पहले, संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष एच.ई. सकर गोबाबा ने संघीय राष्ट्रीय परिषद में बिरला का स्वागत किया। आपको बता दें कि, यूएई की संसद के निमंत्रण पर भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में यूएई के दौरे पर सकती है।

बिरला ने यूएई द्वारा पिछले वर्षों में लोकतंत्र को व्यापक आधार देने तथा संसद में महिलाओं की आयाम देने के साथ साथ भावी आधिक विकास का आधार भी तैयार किया है।

उन्होंने कहा कि विश्व के सभी राष्ट्र आतंकवाद के संबंध में दोनों देशों के साझी चिंता वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक परिवर्त्तन में हमारे सहयोग को नया रूप दे रही है।

बिरला ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा और 2016 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारतीय समृद्धयोग देश के आधिक विकास के साथ-साथ दोनों

देशों को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लोक सभा अध्यक्ष ने निवेशकों को भारत में निवेश के लिए लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत आज विश्व का अग्रणी इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है और डिजिटल इकोनॉमी, मानव संसाधन और स्मार्ट शहरीकरण की दिशा में कोई जाने वाली पहलों से उत्पन्न नए अवसरों का लाभ यूएई की कंपनियों तथा सकती है।

इससे पहले, संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष एच.ई. सकर गोबाबा ने संघीय राष्ट्रीय परिषद में बिरला का स्वागत किया। आपको बता दें कि, यूएई की संसद के निमंत्रण पर भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में यूएई के दौरे पर सकती है।

बिरला ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा और 2016 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारतीय समृद्धयोग देश के आधिक विकास के साथ-साथ दोनों

देशों को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लोक सभा अध्यक्ष ने निवेशकों को भारत में निवेश के लिए लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत आज विश्व का अग्रणी इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है और डिजिटल इकोनॉमी, मानव संसाधन और स्मार्ट शहरीकरण की दिशा में कोई जाने वाली पहलों से उत्पन्न नए अवसरों का लाभ यूएई की कंपनियों तथा सकती है।

बिरला ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा और 2016 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारतीय समृद्धयोग देश के आधिक विकास के साथ-साथ दोनों